राष्ट्रपति के 2024 के अभिभाषण के मुख्य अंश

भारत की राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून, 2024 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रमुख नीतिगत उपलब्धियों और लक्ष्यों को रेखांकित किया। अभिभाषण के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

अर्थव्यवस्था एवं वित्त

- 10 वर्षों में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2021 से 2024 तक भारत की वार्षिक वृद्धि दर औसतन 8% है।
- वैश्विक विकास में भारत का योगदान 15% है। सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा 2023-24 में 1.4 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया जो 2022-23 की तुलना में 35% अधिक है। इन बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो गए हैं। बैंकिंग सुधारों ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में से एक बना दिया है।
- अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन पहली बार दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। जीएसटी अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और व्यापार-व्यवसाय को आसान बनाने में मदद कर रहा है। इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत हुई है।

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा

- कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना के तहत लाभ उन परिवारों को भी दिया जा रहा है जो गरीबी से बाहर आ गए हैं ताकि उन्हें फिर से गरीबी की गर्त में गिरने से रोका जा सके।
- किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा रहा है।
- पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है।
- सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है।
- दलहन और तिलहन पर आयात निर्भरता कम करने के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है।
- सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता बनाने का काम शुरू हो गया है।

उद्योग

- पीएलआई योजनाओं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने में योगदान दिया है।
- सेमीकंडक्टर से लेकर लड़ाकू जेट और एयरक्राफ्ट करियर्स तक के सनराइज क्षेत्रों को मिशन मोड में बढ़ावा दिया जा रहा है। असम में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र मेड इन इंडिया चिप्स का हब बनेगा।
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर

- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन बाजार है। पिछले 10 वर्षों में भारत में एयरलाइन रूट 209 से बढ़कर 605 हो गए हैं। इसका सीधा फायदा टियर-2 और टियर-3 शहरों को हुआ है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति दोगुनी से भी अधिक हो गई है।
- देश के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किया जाएगा।
- सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

अर्पिता मलिक arpita@prsindia.org
ऋत्विक उपाध्याय rutvik@prsindia.org

27 जून, 2024

शहरी एवं ग्रामीण विकास

- पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 10 वर्षों में 3.8 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है।
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में फुटपाथी दुकानदारों को शामिल करने के लिए पीएम स्वनिधि का विस्तार किया जाएगा।
- 10 वर्षों में 21 शहरों में मेट्रो का निर्माण हुआ है।
- पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
- सरकार हमारे शहरों को दुनिया में रहने के लिए सर्वोत्तम स्थान बनाने को प्रतिबद्ध है।

ऊर्जा एवं पर्यावरण

- अक्षय ऊर्जा क्षमताओं को कई गुना बढ़ाया जा रहा है। जलवायु लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिए जाएंगे।
- एक करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकृत किया गया है और उन्होंने रूफटॉप सोलर कनेक्शन स्थापित किए हैं। इससे घरों का बिजली बिल शून्य हो जाता है और उन्हें बिजली बेचकर आय उत्पन्न करने में मदद मिलती है। सरकार ने इस योजना के लिए प्रति परिवार 78,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की है।

स्वास्थ्य

- आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने के काम में तेजी लाई गई है।

शिक्षा एवं खेल

- पिछले दशक में सात नए आईआईटी, सात आईआईएम, 15 एम्स, 16 आईआईआईटी, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। विद्यार्थी अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे।
- परीक्षा संबंधी निकायों में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। इनमें उनकी कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रक्रियाओं के सभी पहलू शामिल होंगे।
- संसद ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग के खिलाफ सख्त कानून बनाया है।
- भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनाने हेतु नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।
- अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने देश के युवाओं की क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद की है।
- भारतीय ओलंपिक संघ 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है।

सामाजिक न्याय

- पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।
- पीएम जनमन को 24,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया गया है। यह योजना पिछड़े आदिवासी समुदायों के विकास पर केंद्रित है।
- आजीविका के अवसरों को सुलभ बनाने के लिए पीएम सुराज पोर्टल के माध्यम से वंचित समूहों को आसान ऋण प्रदान किए जा रहे हैं।
- विकलांग व्यक्तियों को किफायती एसिस्टिव डिवाइस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देशभर में पीएम दिव्याशा केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है।

श्रम एवं रोजगार

- सरकार रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर पैदा कर रही है।
- सरकार श्रमिकों के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत कर रही है।
- डिजिटल इंडिया और पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का उपयोग करके दुर्घटना और जीवन बीमा के कवरेज का विस्तार किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास

- पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए चार करोड़ घरों में से अधिकांश महिला लाभार्थियों को

आवंटित किए गए हैं। जो तीन करोड़ नए घर बन रहे हैं, उनमें से भी ज्यादातर महिला लाभार्थियों को आवंटित किए जाएंगे।

- पिछले दशक में 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 30,000 महिलाओं को कृषि सखी प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं।
- सरकार ने तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू किया है। इसे हासिल करने के लिए एसएचजी को वित्तीय सहायता बढ़ाई जा रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं और उन्हें ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

रक्षा

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे सुधारों ने रक्षा बलों को मजबूत करने में मदद की है।
- ऑर्डनेंस कारखानों में सुधारों से रक्षा क्षेत्र को लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डनेंस कारखानों को रक्षा क्षेत्र के सात उद्यमों में पुनर्गठित किया गया है जिससे उनकी दक्षता में सुधार हुआ है।
- भारत एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है। पिछले वर्ष, लगभग 70% रक्षा खरीद भारतीय मैन्यूफैक्चरर्स से की गई थी। रक्षा बलों ने 500 से अधिक रक्षा वस्तुओं का आयात बंद कर दिया है। रक्षा निर्यात 18 गुना से ज्यादा बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए हो गया है।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं।
- वन रैंक वन पेंशन के तहत 1.2 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

गृह मामले

- भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई, 2024 से लागू की जाएगी। तीन नए आपराधिक कानून न्यायिक प्रक्रिया को गति देने में मदद करेंगे।
- नागरिकता (संशोधन) एक्ट, 2019 के तहत सरकार ने शरणार्थियों को नागरिकता देनी शुरू कर दी है।
- पूर्वोत्तर के अशांत क्षेत्रों से आफ्स्पा को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।
- पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आवंटन चार गुना बढ़ गया है। सरकार ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर को कूटनीतिक प्रवेश द्वार बनाने पर काम कर रही है।

विदेशी मामले

- इंटरनेशनल सोलर एलायंस जैसी पहल पर रिकॉर्ड संख्या में विभिन्न देश भारत के साथ जुड़े हैं।
- इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देने में भारत की अहम भूमिका रही है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।